

6/10/81



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रधानमंत्री से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1989/चैत्र 10, 1911

No. 182] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1989/CHAITRA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(शौद्योगिक विभाग विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

का.शा. 248(प्र)/18फ/शाई.डी.प्रा.ए./89—केंद्रीय मरम्म ने भारत सरकार के भूतपूर्व श्रीद्वि-
गिक विकास मंशान्त्रम के आदेश मं. का.शा. 134(प्र)/19कक्ष/शाई.डी.प्रा.ए./79, तारीख 13 मार्च, 1979
द्वारा तथा उपस्थित आदेश मं. का.शा. 529(प्र)/18फ/प्राई.डी.प्रा.ए./71 तारीख 6 सितम्बर, 1974
द्वारा (जिसे इसके पश्चात उस आदेश कर्ता गया है) गविर, बंद एवं रुग्न उद्योग विभाग, परिवहन बंगाल
सरकार को जिसे इसके पश्चात उस प्राप्तिकृत व्यक्ति कहा गया है मैसर्ज शैंडिया बैलिंग एण्ड काटन

मिल्स सिपिटेट, सीरपुर, पश्चिम बंगाल का (जिस इस इन पश्चात उक्त प्रौद्योगिक उत्क्रम को ले गया है) तारीख 6 मिस्राह, 1971 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध प्रठग करने के लिए प्राविधिक फैसला था।

और केंद्रीय सरकार की यह राय यही फैसले के पद्धतिकारी वा फैसले प्रयोगिक आदेश की उपर्युक्त पांच वर्ष के समान हैं के बाद प्रभागी बना रहा विलिंग प्रोटोकॉल 31 मार्च, 1989 तक की, जिसके प्रस्तुत बहु तारीख भी है भारतिक प्रबंधि के लिए इन तत्त्व रक्षाके लिए प्रभाग-तत्पर पर निर्भय गारी किए थे, (देखिये भारत सरकार, उपांत तितार, गोपोद्धव लिए तितार का गारेग)

मं. का.आ. 512(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./79, तारीख 4 फिस्राह, 1979

मं. का.आ. 749(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./80, तारीख 5 फिस्राह, 1980

मं. का.आ. 684(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./81, तारीख 4 फिस्राह, 1981

मं. का.आ. 125(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./82, तारीख 5 मार्च, 1982

मं. का.आ. 648(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./82, तारीख 4 फिस्राह, 1982

मं. का.आ. 158(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./83, तारीख 4 मार्च, 1983

मं.का.आ. 386(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./83, तारीख 31 मार्च, 1983

मं. का.आ. 937(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./83, तारीख 29 फिस्राह, 1983

मं. का.आ. 170(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./84, तारीख 28 जून, 1984

मं. का.आ. 947(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./84, तारीख 18 फिस्राह, 1984

मं. का.आ. 257(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./85, तारीख 28 मार्च, 1985

मं. का.आ. 119(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./86, तारीख 27 मार्च, 1986

मं. का.आ. 268(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./87, तारीख 30 मार्च, 1987 तथा

मं. का.आ. 325(प्र)/18क्र/प्राई.डो.प्रार.ए./83, तारीख 30 मार्च, 1988।

और केंद्रीय सरकार को यह है फैसले के 15 पांचोंमें से उन पांचोंको उत्क्रम का अध्ययन उक्त प्राविधिक अस्ति द्वारा 31 मार्च, 1990 तक को प्राप्त अवधि के लिए रखा जाए।

प्रतः केंद्रीय सरकार उद्दीपा (लिए प्रोटोकॉल निर्माण, 1951 (1951 से 65) की आदेश 18-क्र की उत्क्रमा (2) द्वारा तरीका द्वारा दूर, पर दिन देते हैं फैसले 31 मार्च, 1990 तक जिसने यह तारीख से अधिकतम है, को और अवधि के लिए प्रभागी बना रखेगा।

[मा.म. 2(14)/80-सी यू एम]

प्रार के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1989

S.O. 248(E)/18AA/IDRA/89.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)/18AA/IDRA/74, dated the 6th September, 1974 as modified by the order No. S.O. 134(E)/18AA/IDRA/79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Bleaching and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1989 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development).

Nos. S.O. 512(E)/18AA/IDRA/79, datee the 4th September, 1979,

S.O. 749(E)/18AA/IDRA/80, dated the 5th September, 1980,

S.O. 684(E)/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981,

S.O. 125(E)/ 18AA/IDRA/82, dated the 5th March, 1982,

S.O. 648(E)/18AA/IDRA/82, dated the 4th September, 1982,

S.O. 158(E)/18AA/IDRA/83, dated the 4th March, 1983,

S.O. 336(E)/18AA/IDRA/83, dated the 31st May, 1983,

S.O. 937(E)/18AA/IDRA/83, dated the 29th December, 1983,

S.O. 47(E)/18AA/IDRA/84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 947(E)/18AA/IDRA/84, dated the 18th December, 1984,

S.O. 257(E)/18AA/IDRA/85, dated the 28th March, 1985,

S.O. 119(E)/18AA/IDRA/86, dated the 27th March, 1986,

S.O. 268(E)/18AA/IDRA/87, dated the 30th March, 1987, and

S.O. 325(E)/18AA/IDRA/88 dated the 30th March, 1988.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto 31st March, 1990.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1990.

[File No. 2(14)/80-CUS]

R.K. SINHA, Jt. Secy.